



Thu - 08 Oct- 2026	Year - 01	Issue 197	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvaani.com
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------

दिवाली पर दुकानदारों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, 'मेरी दुकान, मेरे नाम' योजना शुरू



चंडीगढ़, 8 अक्टूबर: पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात देते हुए 'मेरी दुकान, मेरे नाम' योजना शुरू की है। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैस ने पंजाब भवन में योजना की घोषणा करते हुए कहा कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की दुकानों पर लंबे समय से किराए या लीज पर कारोबार कर रहे पात्र दुकानदार अब मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि जिन दुकानदारों के पास 1 अप्रैल 2020 से पहले 12 वर्षों की कानूनी कब्जेदारी का प्रमाण है, वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित नगर निगम या नगर परिषद कार्यालय में 6 नवंबर 2026 तक जमा किए जा सकेंगे।

40 हजार रुपये रिश्त लेते उत्तरी रेलवे का वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार



चंडीगढ़, 8 अक्टूबर: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत उत्तरी रेलवे में तैनात वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर पंकज भारद्वाज को 40,000 रुपये रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ फिरोजपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने निजी जरूरत के चलते अपने परिचित रेलवे कर्मचारी अमित कुमार को कुछ राशि दी थी। पैसे वापस न मिलने पर उसने अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था। मामले में फिरोजपुर की अदालत ने रेलवे विभाग को अमित कुमार के वेतन का एक-तिहाई हिस्सा काटकर शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए थे।

आरोप है कि अदालत के आदेश को लागू करते हुए वेतन से निर्धारित कटौती करने के बदले वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर पंकज भारद्वाज ने शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये रिश्त की मांग की।

पंजाब में निवेश और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार, 45 दिनों में मंजूरियां; 'हुनर पंजाब' और 'फास्ट-ट्रैक पंजाब' पोर्टल लॉन्च



चंडीगढ़, 8 अक्टूबर: पंजाब को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल, पारदर्शी एवं प्राथमिकता वाला राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को 'हुनर पंजाब' और 'फास्ट-ट्रैक पंजाब' पोर्टल लॉन्च किए। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य निवेशकों को सिंगल विंडो के माध्यम से समयबद्ध मंजूरियां उपलब्ध करवाना, वित्तीय प्रोत्साहनों की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देना तथा उद्योगों को पंजाब के कुशल युवाओं से सीधे जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'फास्ट-ट्रैक पंजाब' पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निवेशक पोर्टल पर मिलने वाली वित्तीय रियायतों और प्रोत्साहनों की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इससे अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने वर्ष

2022 से अब तक करीब 1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े पंजाब के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को पंजाब में ही रोजगार उपलब्ध करवाना और राज्य को दोबारा 'रंगला पंजाब' बनाना है।

'हुनर पंजाब' पोर्टल को उद्योग और युवाओं के बीच एक प्रभावी डिजिटल कड़ी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर पहले ही करीब 1,750 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। कंपनियों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार कुशल युवाओं की तलाश कर सकेंगी और उन्हें सीधे रोजगार प्रदान कर सकेंगी। इससे स्थानीय युवाओं को उनके घरों के नजदीक रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ उद्योगों को आवश्यक मानव संसाधन भी आसानी से उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हुनर पंजाब' केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से संस्थानों की

खोज, भर्ती, इंटरशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण और उद्योग-संस्थान सहयोग को एक ही मंच पर लाया गया है। पोर्टल उद्योगों, विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर उद्योग-संस्थान साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत गैस्ट लेक्चर, फैकल्टी डेवलपमेंट, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे में सहयोग और सीएसआर गतिविधियों जैसी पहल को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विभागों में ई-ऑफिस तथा ऑनलाइन प्रणालियों को लागू किया है। नई डिजिटल व्यवस्था में उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही निर्धारित समय-सीमा, जवाबदेही, हेल्प डेस्क तथा शिकायतों और सवाल के समाधान की सुविधा भी

दिवाली पर पंजाब के लाखों दुकानदारों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, 'मेरी दुकान, मेरे नाम' योजना से मिलेगा मालिकाना हक

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर: पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात देते हुए ऐतिहासिक 'मेरी दुकान, मेरे नाम' योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की इस योजना के तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की दुकानों पर लंबे समय से किराए या लीज पर कारोबार कर रहे पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने का रास्ता साफ हो गया है।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैस ने आज पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि जिन दुकानदारों के पास 1 अप्रैल 2020 से पहले लगातार 12 वर्षों की कानूनी कब्जेदारी का प्रमाण है, वे इस योजना के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल उन हजारों व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो वर्षों से नगर निकायों की दुकानों पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्वामित्व का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था।

मंत्री ने बताया कि पात्र दुकानदार 6 नवंबर 2026 तक संबंधित नगर परिषद या नगर निगम कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध

रखा गया है। आवेदनों की जांच एसडीएम स्तर की समिति द्वारा की जाएगी, जबकि दुकानों की कीमत निर्धारित करने का काम डीसी स्तर की समिति करेगी। इसके बाद संबंधित स्थानीय निकाय की ओर से प्रस्ताव पारित कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हरजोत सिंह बैस ने बताया कि योजना के तहत दुकानदारों को उनकी आय श्रेणी और क्षेत्र के कलेक्टर रेट के आधार पर रियायती कीमत पर मालिकाना हक दिया जाएगा। 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस आवेदकों को कलेक्टर रेट का केवल 12.5 प्रतिशत भुगतान करना होगा। वहीं 3 से 8 लाख रुपये आय वाले एलआईजी वर्ग को 25 प्रतिशत, 8 से 15 लाख रुपये आय वाले एमआईजी वर्ग को 50 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले आवेदकों को कलेक्टर रेट का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। यह रियायती व्यवस्था 50 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली दुकानों पर लागू होगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना में कुछ श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सब-टेनेंट यानी किराएदार के किराएदार इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा पार्कों, सड़कों या सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जे को भी

नियमित नहीं किया जाएगा।

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पेशानी मुक्त रखने का फैसला किया है। पात्रता साबित करने के लिए आवेदक कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें जीएसटी प्रमाणपत्र, बिजली के बिल, वोटर कार्ड तथा अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि वर्षों से कारोबार कर रहे छोटे दुकानदारों को जटिल कागजी प्रक्रिया में उलझने के बजाय आसान तरीके से मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएं।



5 हजार रुपये रिश्त लेते पटवारी और निजी एजेंट रंगे हाथ गिरफ्तार



चंडीगढ़, 8 अक्टूबर 2026: पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर में रिश्तखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और उसके निजी एजेंट को 5,000 रुपये रिश्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पटवार सर्कल बस्ती पीरदाद, जालंधर में तैनात पटवारी विश्वजीत सिंह और निजी एजेंट राकेश कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई है।

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यू राजन नगर, जालंधर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि उसने 4 मरले का एक प्लॉट खरीदा था और उसकी सेल डीड 23 दिसंबर 2024 को अपने छोटे भाई उमेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई थी। इसके बाद वह प्लॉट का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए संबंधित पटवारी के पास गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया में लगातार देरी की जा रही थी। 7 अक्टूबर 2026 को वह दोबारा पटवारी विश्वजीत सिंह के पास पहुंचा। आरोप है कि पटवारी ने उसे अपने निजी एजेंट राकेश कुमार उर्फ सोनू से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद निजी एजेंट ने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के बदले शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्त की मांग की।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने मजबूरी में आरोपी को शुरुआत में 1,500 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन राकेश कुमार ने यह राशि वापस कर दी और अगले दिन पूरी रकम यानी 5,000 रुपये लेकर आने को कहा। इस दौरान रिश्त की मांग को लेकर हुई बातचीत शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड कर ली और बाद में मामले की जानकारी विजिलेंस ब्यूरो को दी।

रिश्त देने के इच्छुक नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर से संपर्क किया। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने मामले में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता को आरोपियों के पास भेजा गया।

SquareNet
Innovation & Excellence

Advertisement

Zoho Mail

Google Workspace

Microsoft 365

Microsoft Solutions Partner

Google Cloud Partner

aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

सेक्टर-44 में चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, कमानीदार चाकू बरामद



पुनीत महाजनचंडीगढ़, 8 अक्टूबर: चंडीगढ़ पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सेक्टर-44 में एक युवक को कमानीदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना किसी वैध परमिट या लाइसेंस के एक कमानीदार चाकू बरामद किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर घूम रहा था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई डब्ल्यू/एसएसपी यूटी चंडीगढ़ के निर्देशों पर, एसपी सिटी की देखरेख तथा एसडीपीओ साउथ गुरजीत कौर के पर्यवेक्षण में थाना-34 की पुलिस टीम द्वारा की गई। अभियान के तहत पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

पुलिस टीम में थाना-34 के एसएचओ इंस्पेक्टर शादीलाल, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार 6186/सीपी, कांस्टेबल हरीश कुमार 1542/सीपी और कांस्टेबल गुरप्रीत 2744/सीपी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2026 को हेड कांस्टेबल नरेश कुमार पुलिस पार्टी के साथ सेक्टर-44 क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।

गश्त के दौरान पुलिस टीम को सेंट जोसेफ स्कूल, सेक्टर-44 के पास एक मुखबिर से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के पास गारबेज साइड रोड पर सफेद टी-शर्ट पहने एक युवक चाकू लेकर घूम रहा है। मुखबिर ने पुलिस को यह भी बताया कि युवक किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करने का फैसला किया।

सेक्टर-44 में चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार, कमानीदार चाकू बरामद



चंडीगढ़, 8 अक्टूबर 2026। कनाडा संभावित इमिग्रेंट्स के लिए एक बार फिर आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। खास तौर पर बड़े महानगरों से बाहर क्षेत्रीय स्तर पर श्रम बाजार की जरूरतों और रोजगार के अवसरों पर बढ़ते फोकस के कारण योग्य आवेदकों के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। यह बात डब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएस ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल बी.एस. संधू (रिटायर्ड) ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि कनाडा के विभिन्न प्रांतों में कुशल कामगारों की जरूरत बनी हुई है। सस्केचेवान जैसे प्रांतों में अपेक्षाकृत कम आबादी और उपलब्ध संसाधनों के चलते पात्र और कुशल इमिग्रेंट्स के लिए अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “क्षेत्रीय अवसरों पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के बीच कनाडा एक आकर्षक इमिग्रेशन डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।”

संभावित इमिग्रेंट्स को बदलती नीतियों और अवसरों की जानकारी देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएस 10 और 11 अक्टूबर को पंजाब तथा चंडीगढ़ में मेगा इमिग्रेशन सेमिनार आयोजित करेगा। 10 अक्टूबर को अमृतसर के होटल बेस्ट वेस्टर्न मेरियन में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे, जालंधर के रमाडा बाय विंथम में दोपहर 3 से शाम 5 बजे और लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में शाम 5 से रात 8 बजे तक सेमिनार होंगे। चंडीगढ़ में 11 अक्टूबर को होटल अरोमा में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल संधू ने कहा कि कनाडा और अन्य प्रमुख देशों में इमिग्रेशन को लेकर रुचि फिर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी योग्यता और पूरी तैयारी वाले आवेदकों के लिए अवसर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आवेदन से पहले पात्रता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

चंडीगढ़ में अब घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं, 124 ऑफलाइन सेवाएं होंगी ऑनलाइन



पुनीत महाजनचंडीगढ़, 8 अक्टूबर: स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ और अधिक आसान एवं सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में शहरवासियों को विभिन्न सरकारी कामों के लिए बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ प्रशासन अब अपनी 124 ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन के कुल 35 विभागों की 556 सेवाएं का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। इनमें से 432 सेवाएं पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अब प्रशासन की ओर से शेष 124 सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। इन सेवाओं के ऑनलाइन होने के बाद नागरिक घर बैठे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यमों से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रशासन के इस कदम से शहरवासियों को सरकारी कार्यालयों में जाकर आवेदन जमा करने, दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने और अपने काम की स्थिति जानने के लिए बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद

है। खासतौर पर बुजुर्गों, कामकाजी लोगों और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं काफी सुविधाजनक साबित हो सकती हैं।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने के साथ-साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति के बारे में भी डिजिटल माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी।

सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का एक बड़ा फायदा यह भी माना जा रहा है कि इससे विभागीय कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम होगी। वर्तमान में कई ऐसी सेवाएं हैं, जिनके लिए नागरिकों को आवेदन जमा करने या संबंधित अधिकारी से संपर्क करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पहुंचना पड़ता है। डिजिटल सुविधा उपलब्ध होने के बाद ऐसे काम ऑनलाइन पूरे किए जा सकेंगे।

प्रशासन का यह कदम ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और नागरिकों को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन जमा करने से लेकर

उसके निपटारे तक विभिन्न चरणों की निगरानी आसान होगी। इससे नागरिकों को यह पता लगाने में भी सुविधा होगी कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है और उसे पूरा होने में कितना समय लग सकता है।

चंडीगढ़ प्रशासन पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवा चुका है। अब बची हुई 124 सेवाओं को भी ऑनलाइन करने की योजना से प्रशासन की डिजिटल सेवा व्यवस्था का दायरा और बढ़ जाएगा। इससे शहरवासियों को अलग-अलग विभागों से संबंधित कार्यों के लिए एक अधिक सुविधाजनक और आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी आधुनिक शहर में नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण प्रशासन और जनता के बीच संपर्क को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंडीगढ़ जैसे योजनाबद्ध शहर में अधिकांश सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से लोगों को समय की बचत के साथ-साथ प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ जवाबदेही तय करने में भी मददगार हो सकता है।

पंचकूला में कांग्रेस का विरोध मार्च, ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ के नारों से गूंजा शहर

पंचकूला, 8 अक्टूबर 2026: ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ और ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत पंचकूला में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। कांग्रेस ने यह मार्च INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर आयोजित किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

विरोध मार्च की शुरुआत सेक्टर-17 स्थित एसबीआई के सामने पार्किंग से हुई। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए और इसके बाद नारेबाजी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती, निष्पक्ष चुनाव और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की, जबकि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में वीरभान मेहता भी विशेष रूप से शामिल हुए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विरोध प्रदर्शन में पंचकूला विधायक चंद्र मोहन, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जिला कांग्रेस पंचकूला अध्यक्ष संजय चौहान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने हाथों में पार्टी के झंडे तथा विभिन्न संदेशों वाली तख्तायां लेकर नारेबाजी की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लगातार ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह अभियान केवल किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी व्यवस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का विश्वास बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब पारदर्शी तरीके से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक सवाल पर संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि मतदाताओं का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहे।

विरोध मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य लोगों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा चुनाव प्रक्रिया

में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को मजबूती से उठाना है।

हालांकि, प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे उनका अभियान प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी।

कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और मताधिकार की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, अधिकारों की रक्षा और संस्थाओं के प्रति विश्वास भी महत्वपूर्ण है।

पंचकूला में आयोजित इस विरोध मार्च के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्षता और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ का संदेश आने वाले दिनों में भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका अभियान जारी रहेगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों तथा संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवालों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।



लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत पंचकूला में कांग्रेस का विरोध मार्च, “वोट बचाओ-देश बचाओ” का दिया नारा



पंचकूला, 8 अक्टूबर 2026। “लोकतंत्र बचाओ सप्ताह” एवं “वोट बचाओ-देश बचाओ” अभियान के तहत पंचकूला में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने तथा मताधिकार की रक्षा की मांग उठाई।

विरोध मार्च की शुरुआत सेक्टर-17 स्थित एसबीआई के सामने पार्किंग स्थल से हुई। यहां बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान “वोट बचाओ-देश बचाओ” के नारे लगाए गए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की। वहीं, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए। वीरभान मेहता भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का मत महत्वपूर्ण है और चुनाव प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को बनाए रखना बेहद जरूरी है।

विरोध मार्च में पंचकूला के विधायक चंद्र मोहन, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जिला कांग्रेस पंचकूला के अध्यक्ष संजय चौहान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। I N D I A गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी प्रदर्शन को व्यापक स्वरूप दिया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने का पूरा अवसर मिल सके। नेताओं ने मताधिकार की रक्षा को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों और चिंताओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना आवश्यक है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “वोट बचाओ-देश बचाओ” के नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और उसके वोट की सुरक्षा तथा उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस अभियान के माध्यम से आम लोगों तक लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को पहुंचाने का भी आह्वान किया।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार “लोकतंत्र बचाओ सप्ताह” के तहत आयोजित कार्यक्रम केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे आम जनता के बीच जाकर मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाएं।

मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़े। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। हालांकि, कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज आगे भी उठाती रहेगी।

मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़े। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। हालांकि, कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015